



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 आषाढ़ 1940 (श10)

(सं0 पटना 609) पटना, मंगलवार, 26 जून 2018

सहकारिता विभाग

अधिसूचना

21 जून 2018

सं० 09/नि.फ.बी.(को.)-33/2018-5389—राज्य सरकार द्वारा “बिहार राज्य फसल सहायता योजना” के लिए दी गई स्वीकृति एवं इस योजना के लिए प्रचारित दिशा-निदेश तथा सहकारिता विभाग के संकल्प संख्या-4989 दिनांक 08.06.2018 द्वारा योजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति (SLCC) की दिनांक 11.06.2018 को सम्पन्न बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में बिहार राज्य में खरीफ 2018 मौसम से “बिहार राज्य फसल सहायता योजना” को निम्नरूपेण अधिसूचित किया जाता है :-

(क) इस योजना हेतु अगहनी धान एवं भदई-मकई फसलों को अधिसूचित किया जाता है। अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा खरीफ 2018 मौसम के लिए अधिसूचित फसलों की सूची के अनुसार अगहनी धान का फसल राज्य के 38 जिलों के 527 अंचलों (भागलपुर के नवगछिया, बिदुपुर, गोपालपुर, नारायणपुर, इस्माईलपुर, रंगराचौक एवं खरीक अंचलों को छोड़कर) के सभी ग्राम पंचायतों एवं भदई-मकई का फसल राज्य के 38 जिलों के सभी ग्राम पंचायतों में अधिसूचित किया जाता है।

(ख) आच्छादित किसान :-

(i) रैयत किसान :- ऐसे सभी किसान जो अपनी रैयती भूमि पर खेती स्वयं करते हो।

(ii) गैर-रैयत किसान :- ऐसे सभी किसान जो दूसरे रैयतों की भूमि पर खेती करते हो।

नोट :- ऐसे किसान जो अपनी रैयती भूमि पर खेती करने के साथ-साथ दूसरे रैयतों की भूमि पर खेती करते हैं, उन्हें इस योजना के तहत आच्छादित होने के दृष्टिगत रैयत अथवा गैर-रैयत में से एक ही विकल्प चुनना होगा।

गैर-रैयत किसान श्रेणी में एक परिवार (सामाजिक-आर्थिक जनगणना के आधार पर) से एक ही सदस्य इस योजना के तहत निबंधन करा सकेंगे।

(ग) आवेदन-पत्र तथा पात्र किसानों का ऑन-लाईन निबंधन :-

इस योजना के तहत सभी प्रकार के इच्छुक किसानों को खरीफ-2018 मौसम में योजना के पोर्टल पर ऑन-लाईन निबंधन कराना अनिवार्य है। ऑन-लाईन निबंधन के द्वारा ही आवेदन मान्य होगा तथा अनिबंधित किसानों का आवेदन अमान्य होगा।

**2. योजना से संबंधित महत्वपूर्ण निदेश :-****(i) इन्डेमनिटी स्तर एवं थ्रेशहोल्ड उपज :-**

बिहार राज्य में विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों के उत्पादन का कार्य राज्य के किसानों के लिए उच्च जोखिम का है, अतः किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए इस योजना में 70% इन्डेमनिटी स्तर का प्रावधान किया गया है।

थ्रेशहोल्ड (Threshold) उपज पिछले 07 वर्षों की औसत उपज (राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित आपदा वर्ष को छोड़कर) एवं इन्डेमनिटी स्तर से गुणा करने पर प्राप्त होगी।

थ्रेशहोल्ड (Threshold) उपज की गणना के प्रयोजनार्थ पूर्व वर्षों के उपज दर के आँकड़ों की अनुपलब्धता की स्थिति में उच्च स्तर के लिए निर्धारित उपज दर उक्त अधिसूचित क्षेत्र के लिए भी मान्य होगा।

**(ii) आच्छादित/सहायता राशि की अधिसीमा :-**

(क) थ्रेशहोल्ड उपज दर की तुलना में वास्तविक उपज दर में 20% तक ह्रास की स्थिति में 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम दो (02) हेक्टेयर तक कुल 15,000 रुपये सहायता राशि अनुमान्य है।

(ख) थ्रेशहोल्ड उपज दर की तुलना में वास्तविक उपज दर में 20% से ज्यादा ह्रास की स्थिति में 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम दो (02) हेक्टेयर तक कुल 20,000 रुपये सहायता राशि अनुमान्य है।

**(iii) कार्यान्वयन हेतु समय सीमा :-**

इस योजना के क्रियाकलापों की समय-सीमा का सामान्यतः निम्न प्रकार से अनुपालन किया जाएगा :-

क्र०सं०	क्रियाकलाप	खरीफ मौसम के लिए
1.	पात्र किसानों का ऑन-लाईन निबंधन	31 जुलाई तक
2.	फसल कटनी प्रयोग के सम्पादन तथा इसके फलाफल के ऑन-लाईन पोर्टल में प्रविष्टि करने की अंतिम तिथि	28 फरवरी
3.	सहायता राशि की गणना	15 मार्च
4.	सहायता राशि का भुगतान	मार्च/अप्रैल

**(iv) फसल कटनी प्रयोग :-**

(क) अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार के निदेशन एवं पर्यवेक्षण में धान एवं मकई दोनों फसलों के लिए फसल कटनी प्रयोगों का सम्पादन एकांश श्रृंखला अन्तर्गत प्रति फसल प्रति पंचायत न्यूनतम 04 की संख्या में किया जाएगा।

(ख) फसल कटनी प्रयोगों के फलाफल के आधार पर प्रति हेक्टेयर उपज दर निर्धारित होगी। यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र में फसल कटनी प्रयोग सम्पादित नहीं हो सका हो तो निकटवर्ती क्षेत्र अथवा उच्च स्तर पर निर्धारित उपज दर उक्त क्षेत्र हेतु भी मान्य होगी।

(ग) फसल कटनी प्रयोगों का सम्पादन पूर्ण पारदर्शी तरीके से पूर्ण प्रचार-प्रसार करते हुए सुनिश्चित कराया जाएगा।

(घ) फसल कटनी प्रयोगों के आधार पर उपज दर की ऑन-लाईन प्रविष्टि योजना पोर्टल पर सुनिश्चित की जाएगी।

(ङ) फसल कटनी प्रयोगों के ससमय सम्पादन हेतु कृषि सलाहकार/कृषि समन्वयक की सेवाएँ ली जा सकेंगी।

(च) फसल कटनी प्रयोगों के सम्पादन के समय संबंधित पंचायत के पैक्स के अध्यक्ष भी सह-प्रेक्षक (Co-observer) के रूप में उपस्थित रह सकेंगे।

**(v) उपज दर में ह्रास तथा सहायता दर का मूल्यांकन :-**

(क) उपज दर में ह्रास का मूल्यांकन निर्धारित थ्रेशहोल्ड उपज की तुलना में वर्तमान मौसम में फसल कटनी प्रयोग के फलाफल के आधार पर निर्धारित वास्तविक उपज दर में हुए ह्रास के आधार पर किया जाएगा।

(ख) अधिसूचित क्षेत्रान्तर्गत निबंधित सभी किसानों के लिए उपज दर में ह्रास के अनुरूप सहायता दर का निर्धारण किया जाएगा।

**3. योजना से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण निदेश :-****(क) पात्र किसानों का ऑन-लाईन निबंधन की प्रक्रिया**

(i) रैयत श्रेणी के किसानों को निबंधन कराने हेतु अन्य सूचनाओं की प्रविष्टि के साथ-साथ व्यक्तिगत पहचान-पत्र, अपना फोटोग्राफ, बैंक पासबुक, आवासन का प्रमाण-पत्र, आवेदक के नाम का हाल का बना भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र, जिस फसल हेतु आच्छादित होने की इच्छा रखते हों उक्त फसल की बुआई का स्वघोषणा-पत्र (रकबा सहित), को अपलोड करना अनिवार्य होगा।

- (ii) गैर-रैयत श्रेणी के किसानों को निबंधन कराने हेतु अन्य सूचनाओं की प्रविष्टि के साथ-साथ व्यक्तिगत पहचान-पत्र, अपना फोटोग्राफ, बैंक पासबुक, आवासन का प्रमाण-पत्र, दूसरे की जमीन पर खेती करने संबंधी स्वघोषणा-पत्र, जिसमें रकबा सहित बुआई की गई फसल की विवरणी अंकित हो तथा उक्त स्वघोषणा-पत्र किसान सलाहकार या वार्ड सदस्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, को अपलोड करना अनिवार्य होगा।
  - (iii) सभी श्रेणी के किसानों के ऑन-लाईन निबंधन हेतु "आधार" संख्या की प्रविष्टि किया जाना अनिवार्य होगा।
  - (iv) इस योजना हेतु निर्धारित पात्रता के अनुरूप निबंधित किसान नहीं पाए जाने पर उनका निबंधन रद्द किया जा सकेगा।
  - (v) ऑन-लाईन प्रविष्टि आँकड़ों का सत्यापन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा पर्यवेक्षकों/ पंचायत स्तरीय कर्मियों से कराया जाएगा। इस हेतु प्रत्येक पंचायत का एक प्रभारी कर्मी नामित रहेगा। सत्यापन के फलाफल का पंचायत प्रभारी द्वारा ऑन-लाईन पोर्टल में प्रविष्टि करना होगा।
  - (vi) निबंधित किसानों में से 2% किसानों का random सत्यापन जिलास्तरीय समन्वय समिति के माध्यम से कराया जा सकेगा।
- (ख) सहायता राशि की अनुमान्यता का निर्धारण-
- (i) वास्तविक उपज में ह्रास की मात्रा (प्रतिशत में) निम्न प्रकार से निर्धारित की जाएगी -  
 श्रेणहोलड उपज - वास्तविक उपज

X 100

श्रेणहोलड उपज

- (ii) वास्तविक उपज में ह्रास की मात्रा (प्रतिशत) के अनुसार सहायता राशि निर्धारित की जाएगी।
- (ग) सहायता राशि की स्वीकृति एवं भुगतान :-
- (i) प्रखण्ड अंतर्गत निबंधित किसानों के लिए फसल कटनी प्रयोग के फलाफल के आधार पर अनुमान्य सहायता राशि ऑन-लाईन पोर्टल पर स्वतः परिकलित (calculated) एवं परिलक्षित होगी। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, प्रखण्ड सांख्यिकी पर्यवेक्षक तथा अन्य पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी की सहायता से ऑन-लाईन पोर्टल में फसल कटनी प्रयोगों के फलाफल तथा पूर्व वर्षों के उपज दर के आँकड़ों की प्रविष्टियों की शुद्धता का अनुश्रवण कराया जाएगा तथा उपज दर में असमान्य वृद्धि अथवा ह्रास की स्थिति में संबंधित प्रविष्टियों/आँकड़ों तथा गणना की जाँच कराते हुए संतुष्ट भी हो लेंगे।
  - (ii) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी तत्पश्चात् किसानवार देय सहायता राशि की **system** से स्वतः **generated** तत्संबंधी एडभाईस हस्ताक्षरोपरान्त संबंधित जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक (जो जिले, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के क्षेत्र अंतर्गत नहीं हैं, वैसे जिलों में बिहार राज्य सहकारी बैंक लि० की शाखाओं) को प्राप्त करायेंगे।
  - (iii) सहायता राशि नोडल विभाग द्वारा बिहार राज्य सहकारी बैंक लि० के माध्यम से संबंधित जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को उपलब्ध करायी जाएगी।
  - (iv) जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक/बिहार राज्य सहकारी बैंक लि०, एडभाईस में अंकित किसान के खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से हस्तांतरित करना सुनिश्चित करेंगे।

4. (क) इस योजना के तहत अनुमान्य सहायता राशि फसल कटनी प्रयोग के फलाफल पर आधारित फसल उत्पादन में हुए ह्रास के लिए प्रदान होनी है। फसल अवधि के दौरान हुए नुकसान अथवा सम्भावित नुकसान से फसल को बचाने हेतु आपदा प्रबंधन के तहत संचालित कृषि इनपुट अनुदान योजना अथवा डीजल सब्सिडी योजना से यह योजना सम्बद्ध नहीं होगी तथा इस योजना का लाभ उक्त दोनों योजना के तहत लाभान्वित किसानों को भी अनुमान्य होगा।

(ख) जिला सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा फसल कटनी प्रयोगों के सम्पादन का सही-सही प्रबंधन, तदनुसार आँकड़ों की प्रविष्टि, वास्तविक उपज दर निर्धारण एवं श्रेणहोलड उपज दर की गणना हेतु पूर्व वर्षों के उपज दर के आँकड़ों की प्रविष्टियों की शुद्धता सुनिश्चित करायी जाएगी

(ग) जिलास्तरीय समन्वय समिति द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा के साथ-साथ फसल कटनी प्रयोगों के सम्पादन का सही-सही प्रबंधन, आँकड़ों की प्रविष्टियों की शुद्धता, उपज दर निर्धारण आदि की भी समीक्षा की जाएगी तथा अनापेक्षित फलाफल की स्थिति में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा की गई कार्यवाहियों के आलोक में यथा आवश्यक निर्देश दिया जा सकेगा।

(घ) इस योजना में सहायता राशि की अनुमान्यता अथवा भुगतान संबंधी विवादों के निपटारा हेतु जिला स्तर पर गठित जिलास्तरीय समन्वय समिति सक्षम होगी।

(इ) योजना का प्रचार-प्रसार दैनिक समाचार-पत्र के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कराते हुए, टेलीविजन के माध्यम से तथा क्षेत्रीय स्तर पर कार्यशाला एवं बैठक आयोजित कराते हुए व्यापक रूप से किया जाएगा। साथ ही, पंचायत स्तर पर पैक्सों के द्वारा बैठक/गोष्ठी आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जा सकेगा।

5. विभागीय संकल्प संख्या-4989 दिनांक 08.06.2018 द्वारा जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय समन्वय समिति द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन का पूर्ण अनुश्रवण योजना के दिशा निदेश में अंकित प्रावधानों के आलोक में सुनिश्चित किया जाएगा। जिला सहकारिता पदाधिकारी जो उक्त जिला स्तरीय समन्वय समिति के सदस्य सचिव हैं, के द्वारा जिला पदाधिकारी के निदेशन में योजना के दिशा-निदेश के अनुरूप यथाअपेक्षित सभी कार्रवाइयाँ ससमय क्रियान्वित कराया जाना सुनिश्चित करायेंगे।

6. राज्य सरकार द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन के संबंध में आवश्यकतानुसार दिशा-निदेश निर्गत किया जा सकेगा।

7. अधिसूचना में अवर्णित टर्म्स और कंडिशनस बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रचारित दिशा-निदेश के अनुसार किया जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
अतुल प्रसाद,  
सरकार के प्रधान सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 609-571+20-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>